युवा स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर फिट रहें और प्रदेश के विकास में योगदान दें : मुख्यमंत्री

'राज्य सरकार 92 हजार नियुक्तियां दे चुकी, इस माह भी 20 हजार युवाओं को मिलेंगी नौकरी'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से आव्हान किया कि, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए फिट रहें तथा प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दें, जिससे प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सके। अगर प्रदेशवासी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान कई गुना आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को ''रन फॉर विकसित राजस्थान'' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमर जवान ज्योति से ''रन फॉर विकसित राजस्थान'' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को ''रन फॉर विकसित राजस्थान'' में युवाओं के साथ दौड़े।

- पिछली कांग्रेस सरकार में पेपरलीक हुए; हमने 296 भर्ती परीक्षाएं करवाईं, इनमें से एक का भी पेपरलीक नहीं हुआ : भजनलाल शर्मा

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, हमारी सरकार ने बीते दो वर्ष में हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय लिए। विशेषकर युवाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस कदम उठाए है। जबकि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदते हुए अनेक पेपरलीक के प्रकरण हुए थे, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में 296 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई, उनमें से एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए। राज्य सरकार ने बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 92 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रदान की है तथा 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस माह भी लगभग 20 हजार पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है।राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रही है, जिससे वे अब रोजगार प्रदाता भी बन रहे है।

युवा मामलात एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दो वर्ष में हर क्षेत्र में काम किया हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हमारी सरकार राज्य को भारत में अग्रणी स्टेट बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इससे पहले भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान भी किया। इस दौरान विधायक कुलदीप, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल नीरज के. पवन सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे।

राजस्थान में परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना मजबूत कर रही सरकार

- पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चार स्टेशन टू-लेन सड़कों से जुड़े, 8 स्टेशनों का काम शीघ्र होगा पूरा
- 112 करोड़ रुपये की लागत से 59 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़कों का निर्माण
- 564 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन विकसित कर रही है राज्य सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं प्रभावी नीतियों के फलस्वरूप राजस्थान में परिवहन तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार द्वारा माल परिवहन लागत में कमी लाने एवं औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गत 2 वर्षों में किए गए प्रयास अब मूर्त रूप ले रहे है।

माल परिवहन को और अधिक सुलभ, त्वरित एवं किफायती बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के प्रदेश से गुजरने वाले खंड में सभी फ्रेट कॉरिडोर स्टेशनों को ऑल-वेदर टू-लेन सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 नवीन स्टेशनों तक कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए लगभग 112 करोड़ रुपये की लागत से 59 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इनमें से चार स्टेशनों- किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज एवं बनास स्टेशनों तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अन्य आठ स्टेशनों, श्रीमाधोपुर, सराधना, हरिपुर, चंडावल, जवाली, बिरोलिया, साखून एवं स्वरूपगंज स्टेशनों को भी टू-लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य जारी है। इन सड़कों के निर्माण से उद्योगों को कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सुगमता मिलेगी साथ ही लागत में भी कमी आएगी। लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होने के कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा तथा रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाने के लिए बधाल डीएफसीसी टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जोड़ने के लिए 95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही मुख्य जिला सड़क-81 पर बागावास बाईपास के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। यहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

इसके अतिरिक्त मंडा रीको औद्योगिक क्षेत्र को लालासर (एमडीआर-81) से जोड़ने के लिए 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे 1504 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से लगभग 564 किलोमीटर का महत्त्वपूर्ण खंड राजस्थान से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 12 स्टेशन पूर्व में समुचित सड़क सुविधा से वंचित थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद इन सभी स्टेशनों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम प्रगति पर है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर व लायन सफारी बनी आकर्षण का केन्द्र

- 20 दिनों में 30 हजार से ज्यादा सैलानियों ने लिया रोमांचक अनुभव

जयपुर। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदलते मौसम के सुहावने मिजाज और छुट्टी के दिन के उत्साह ने पर्यटकों को प्रकृति की गोद में खींच लाया। कुल 4025 सैलानियों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

इस दौरान लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रहीं। उप वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 552 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और शेर व बाघ की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गौरतलब है कि पर्यटन सीजन में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है यही कारण है कि विगत 20 दिनों में 30 हजार से अधिक सैलानी टाइगर व लायन सफारी का रोमांचक अनुभव उठा चुका हैं।

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़, रेंजर शुभम शर्मा ने रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रैंज अधिकारी शुभम शर्मा की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई।

युवक से मोबाइल छीन भागे बदमाश

जयपुर। गांधी नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश पैदल फोन पर बात करते जा रहे युवक के हाथ पर झपट्टा मार आईफोन छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से पीड़ित घबरा गया और बाइक के नंबर नहीं देख सका। पीड़ित ने थाने पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास नाकाबंदी भी की। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरु कर दी है। हेड कॉन्स्टेबल भरतलाल ने बताया कि रोताश सिंह (33) डीग,कुम्हेर निवासी शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे नारायण सिंह सर्किल से नगर निगम कार्यालय की तरफ पैदल मोबाइल फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। इसी दौरान सुबोध कॉलेज के गेट के पास रॉग साइड से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और आईफोन -13 प्रो छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन बाइक सवार बदमाश तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

अशोक गहलोत का दावा ''90 प्रतिशत अरावली खत्म हो जाएगी'' पूरी तरह भ्रामक और असत्य : राजेन्द्र राठौड़

'अरावली श्रृंखला के मानदंड कांग्रेसराज में लागू हुए थे, वर्ष 2003 में जिलेवार नक्शे भी मुख्यमंत्री रहते गहलोत ने जारी किए थे'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भाजपा के पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दावा पूरी तरह भ्रामक और झूठा है कि ''90 प्रतिशत अरावली खत्म हो जाएगी।'' अरावली पर्वतमाला जैसे गंभीर पर्यावरणीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के विरूद्ध भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब ढाई अरब साल पुरानी, विश्व की सबसे प्राचीन 700 किमी लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर का मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू-आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। यह व्यवस्था पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक है।

राजेन्द्र राठौड़

- अरावली सुरक्षित है, सरकार का रुख स्पष्ट है-अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और कानून का पालन सर्वोपरि रहेगा : राठौड़
- राठौड़ ने कहा कि गत 18 दिसंबर को गहलोत ने ''अरावली बचाओ'' के नाम पर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा और प्रोफाइल पिक्चर बदली। परंतु राहुल गांधी, खरगे, पायलट अथवा डोटासरा ने अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं बदली। यह दर्शाता है कि जो दावा गहलोत कर रहे हैं, उसमें स्वयं उनकी पार्टी का समर्थन भी नहीं है।''

राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि अरावली क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा पूरे अरावली क्षेत्र में से केवल लगभग 2.56 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित, नियंत्रित और कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्टरी रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक मापन और सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अरावली के नष्ट होने की बात करना अशोक गहलोत का सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास है।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, कमेटी की बातचीत में यह स्पष्ट तथ्य सामने आए कि अरावली क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करने की औपचारिक परिभाषा केवल राजस्थान के पास थी, जो 2002 की कमेटी रिपोर्ट और रिचर्ड मर्फ (1968) के लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इस परिभाषा के अनुसार स्थानीय ऊँचाई से 100 मीटर या उससे अधिक उठने वाली पहाड़ियों और उनकी ढलानों पर खनन प्रतिबंधित है और राजस्थान 9 जनवरी 2006 से इसका पालन कर रहा है। यानी तब से ऐसी पहाड़ियों में कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में सीमित कर दिया है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि यही मानदंड कांग्रेस शासनकाल में तय और लागू हुआ था। गत 19 अगस्त 2003 को जिलेवार नक्शे तैयार करने के निर्देश भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जारी किए गए थे। वर्षों तक इस परिभाषा को लागू रखने के बाद आज इसे गलत बताना न्यायिक फैसले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं तो और क्या है?

राठौड़ ने कहा कि गत 18 दिसंबर को अशोक गहलोत ने ''अरावली बचाओ'' के नाम पर सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, न कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और न ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यह साफ दर्शाता है कि जिस अभियान का दावा किया जा रहा है, उसमें स्वयं उनकी पार्टी का समर्थन भी उनके साथ नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता भी उनके साथ खड़े न हों, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक दिखावा है। अरावली जैसे संवेदनशील विषय पर प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

राठौड़ ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन नहीं बढ़ेगा बल्कि और अधिक सख्ती आएगी। राजस्थान के राजसमंद में 98.9 प्रतिशत, उदयपुर में 99.89 प्रतिशत, गुजरात के साबरकांठा में 89.4 प्रतिशत और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.07 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र खनन से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यान, इको-सैंसिटिव ज़ोन, रिज़र्व एवं प्रोटेक्टेड फ़ॉरेस्ट और वेटलैंड्स में खनन पूरी तरह बंद है। वर्तमान में अरावली क्षेत्र के 37 ज़िलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.19 प्रतिशत (277.89 वर्ग किमी) हिस्सा ही कानूनी खनन पट्टों के अंतर्गत है जिसमें भी लगभग 90 प्रतिशत खनन राजस्थान, नौ प्रतिशत गुजरात और एक प्रतिशत हरियाणा तक सीमित है। इसलिए 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियों के खत्म होने की बात कानूनी और भौगोलिक रूप से पूरी तरीके से असत्य है।

निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया

जयपुर। श्रीअमरापुर स्थान में श्री अमरापुर सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। शिविर के अंतर्गत डॉक्टरों की निःशुल्क परामर्श के साथ - साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ हेल्थ परामर्शदाता आदि की सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। जिसमें सैकड़ो भक्त लाभान्वित हुए। संतो ने बताया कि विशेषज्ञ डॉ के परामर्श से जटिल एवं गंभीर बीमारियों का समाधान एक ही स्थान पर सुगम प्रकार से मिल सके ,इसलिए इस प्रकार के सेवा शिविरों का आयोजन समय- समय पर किया जाता है। शिविर में डॉक्टर सुभाष राजपूत, डॉ. आशा लता,डॉ. संजय, डॉ. राजेश जोगी, एवं समाजसेवी तरुण मेठवानी, संजीत सिंह, रुक्मणि अमरवानी साहित स्वनेत्र आई टीम एवं अन्य विशेषज्ञों ने सेवाएं दी।

कार्यालय-उपायुक्त, सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास)
क्रमांक-एफ-53/डी.सी./एसएनजैड/ननिज/2025-26/7600
सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति दिनांक-15/12/25
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा लक्ष्मी कॉलोनी, के.एल.वाल्मिकी रोड, सांगानेर जिला जयपुर का उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
क्र.सं.-1, आवेदक का नाम-श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री संतोष कुमार शर्मा, भूखण्ड का स्थल-लक्ष्मी कॉलोनी, के. एल. वाल्मिकी रोड, सांगानेर जयपुर, वार्ड नं.-90, अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गगज)-149.74, योजना-उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण
अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।
(डॉ. रवि कुमार गोयल) आर.ए.एस
उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन), नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी, जयपुर)
क्रमांक- एफ-55 ()वि.जोन/ ज.न.नि./2025/3394 दिनांक: 20.12.2025
सार्वजनिक सूचना:
भूखंड सं. 56, स्कीम नं.11 झोटवाड़ा, जयपुर (नेशनल गृह.नि.स.स) का श्रीमती प्रेम कँवर पत्नि श्री ओमप्रकाश सिंह को दिनांक 19.04.2002, क्षेत्रफल 200 वर्गगिज भूमि का लीज डीड पट्टा जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा रजि. उपहार पत्र के आधार पर दिनांक 24.01.2022 को भूखंड श्री रघुवीर सिंह शेखावत एवं श्री रविन्द्र सिंह शेखावत पुत्रान ओमप्रकाश सिंह के पक्ष में कर दिया। तत्पश्चात श्री रघुवीर सिंह शेखावत एवं श्री रविन्द्र सिंह शेखावत पुत्रान ओमप्रकाश सिंह ने रजि. विक्रय पत्र के आधार पर भूखंड सं. 56 (साउथ पार्ट) स्कीम नं. 11, झोटवाड़ा जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगिज, श्रीमती गणेशी देवी पत्नि श्री लाला राम को बेचान कर दिया। आवेदिका श्रीमती गणेशी देवी पत्नि श्री लाला राम द्वारा भूखंड सं. 56 (साउथ पार्ट) स्कीम नं. 11, झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगिज का उपविभाजन अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उपविभाजन की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त: विद्याधर जोन, नगर निगम जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत नींदडदा, पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक :-103 दिनांक :-15/12/25
ई-निविदा सूचना संख्या - 07/2025-26
पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत नींदडदा में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नींदडदा, पं.स.स.मा. जिला-सवाई माधोपुर
NIB- ZSM2526A0708
UBN- ZSM2526WSOB00821 to 22
प्रशासक, ग्राम पंचायत नींदडदा, पं.स.स.मा. जिला-सवाई माधोपुर

एलईडी वैन से गांव-गांव पहुंच रहीं सरकार की उपलब्धियां

- विकास रथ बने ग्रामीणों के आकर्षण का केन्द्र, योजनाओं की जानकारी से हो रहे रूबरू

जयपुर। वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 2 साल : नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जयपुर जिले में विकास रथों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विकास रथ (एलईडी वैन) द्वारा जिले की विभिन्न विधानसभाओं के गांव-गांव तक पहुँचकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुँचाई जा रही है।

इसी कड़ी में रविवार को जिले की पांच विधानसभाओं के विभिन्न ग्रामों में एलईडी वैन के माध्यम से विकास रथों ने भ्रमण कर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। एलईडी स्क्रीन पर ऑडियो-विजुअल प्रस्तुतियों के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बीते दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में लिए गए निर्णयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी एवं रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया।